

राज्य के नवासियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश बरकरार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने "सामाजिक-आर्थिक" कारकों के आधार पर वशिष्ट नौकरी की भरतियों के लिये राज्य के नवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने के हरियाणा सरकार के नरिणय को रद्द करने के [उच्च न्यायालय](#) के नरिणय को बरकरार रखा और इसे एक अनुचति कार्रवाई माना।

मुख्य बदि:

- [हरियाणा करमचारी चयन आयोग](#) की याचिका को [पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय](#) के उस नरिणय को चुनौती देने के लिये खारजि कर दिया गया है, जसिमें वर्ष 2023 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET 2023) के दौरान हरियाणा के नवासियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने वाली राज्य अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने नई परीक्षा आयोजति करने का आदेश दिया।
- इस "सामाजिक-आर्थिक" मानदंड के तहत हरियाणा सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर [हरियाणा के नवासियों को अतिरिक्त महत्त्व](#) प्रदान किया।
- इन शर्तों में परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी सरकारी करमचारी न होना तथा सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपए से कम होना शामिल है।

अधवास आरक्षण

- एक ओर संवधान की धारा 16(2) में कहा गया है कि "राज्य के अधीन कसिी नयोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, नवास या इनमें से कसिी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे वभिद किया जाएगा।"
- दूसरी ओर, इसी अनुच्छेद का खंड 4 कहता है कि "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पछिड़े हुए नागरिकों के कसिी वर्ग के पक्ष में जसिका प्रतनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नयुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबंध करने से नविवरति नहीं करेगी।"
- लेकिन ये प्रावधान सरकारी नौकरियों के मामले में लागू हैं।
- [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है।
- इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सीमाएँ लगाना कसिी व्यक्त के अपनी पसंद की वृत्ति, व्यापार या कारोबार में शामिल होने के संवधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसा कि [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) में कहा गया है।
- इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा कि "हरियाणा राज्य से असंबद्ध नागरिकों के समूह को द्वितीयक दर्जा देने (secondary status) और आजीविका कमाने के उनके मौलिक अधिकारों में कटौती करके [संवधानिक नैतिकता](#) (constitutional morality) की अवधारणा का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है।
- [आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय](#) ने भी माना है कि वर्ष 2019 में पारति आंध्र प्रदेश का अधवास के आधार पर आरक्षण प्रदान करने वाला वधियक "असंवधानिक हो सकता है", हालाँकि अभी मेरटि या योग्यता के आधार पर इस पर सुनवाई किया जाना शेष है।